

प्रभार  
उपस्थ विभाग

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O.—250  
KM—30  
CPB—220

पुरा किया

सं. 44]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925

No. 44]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

वित्त मंत्रालय

प्रभारी

रा० वि० ए०

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

सं. 30/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 81(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है और सा. का. नि. सं. 99 (अ), दिनांक 11 फरवरी, 1999 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 फरवरी, 1999 को प्रकाशित भारत के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/1999-सीमा शुल्क के अधिकृत करते हुए एतद्वारा पुराने कम्प्यूटर और कम्प्यूटर परिधीय जिनमें प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, मॉनीटर, कीबोर्ड तथा स्टोरेज यूनिट शामिल हैं, को सीमा शुल्क के सम्पूर्ण अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत इस पर उद्ग्राह्य सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क से छूट प्रदान करती है, जबकि इन्हें निम्नलिखित द्वारा दान के रूप में प्राप्त किया जाए :-

- (i) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित विद्यालय ;
- (ii) किसी संगठन द्वारा गैर-वाणिज्यिक आधार पर संचालित कोई शैक्षणिक संस्थान ;
- (iii) पंजीकृत धर्मार्थ अस्पताल ;
- (iv) सार्वजनिक पुस्तकालय ;
- (v) लोक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास स्थापन ;
- (vi) केन्द्र सरकार का किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित सामुदायिक सूचना केन्द्र ;
- (vii) केन्द्र सरकार का किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र का किसी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित प्रौढ शिक्षा केन्द्र या
- (viii) केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का कोई संगठन ;

बशर्ते कि भारत के बाहर से दाता, उक्त संगठन, उस प्रक्रिया के पालन करने का, जो उक्त माल को दाता के एकक से माल की पत्तन/ विमान पत्तन अथवा अंतर्देशीय आयात डिपो से उस के परिसरों को परिवहन करने के लिए दाता के एकक पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विहित की जाए; वधनबद्ध करता है और ऐसे माल का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और उक्त माल का दाता से उसे प्राप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उक्त सहायक आयुक्त या उप आयुक्त की अनुज्ञा के बिना विक्रय, व्ययन, दान, उधार, अदला-बदली या उसे अलग नहीं किया जाएगा व पांच वर्ष की उक्त अवधि के दौरान क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा यादृच्छिक आधार पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कम्प्यूटर वस्तुतः वहीं हैं तथा इन्हें दूसरे कार्यों में या अनाधिकृत प्रयोग नहीं किया गया है, निरीक्षण कर सकता है।

बशर्ते कि जहां आयात एक संगठन द्वारा किया जाता है लेकिन वह केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय संस्था द्वारा संचालित न हो, दाता एकक, केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त संगठन केन्द्र सरकार या उक्त राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा यह गैर-वाणिज्यिक आधार पर संचालित की जाती है।

[फा. सं. 528/133/03-सी.शु. (टी.यू.)]

वी. केजो, अवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2004

No. 30/2004-CUSTOMS

**G.S.R. 81(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 18/1999-CUSTOMS, dated the 11th February, 1999, published in the Gazette of India, Extraordinary vide, G.S.R. No. 99(E), dated the 11<sup>th</sup> February, 1999, hereby exempts second hand computers and computer peripherals including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage unit from the whole of duty and additional duty of customs leviable thereon under the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when received as donation by —

- (i) a School run by the Central Government or, Government of a State or, a Union territory or, a local body;
- (ii) an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization;
- (iii) a Registered Charitable Hospital;
- (iv) a Public Library;

- (v) a Public Funded Research and Development Establishment;
- (vi) a Community Information Centre run by, the Central Government or, Government of a State or, a Union territory or, local body;
- (vii) an Adult Education Centre run by the Central Government or, Government of a State or, a Union territory or, a local body, or
- (viii) an organisation of the Central Government or, a Government of a State or, a Union territory,

from a donor outside India, subject to the condition that the said organisation undertakes to observe the procedure prescribed by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction, for transport of the said goods from the Port or Airport or Land Custom Station or Inland Container Depot to its premises and such goods shall not be used for any commercial purposes, and shall not be sold, disposed of, gifted, loaned, exchanged or parted with, without the permission of the said Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs, within a period of five years from the date of receipt of the said goods and during the said period of five years, the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may inspect these organisations on random basis, to ensure that the computers are actually there and have not been diverted or put to unauthorized use:

Provided that where the imports are made by an organisation but not run by the Central Government, Government of a State or Union territory or a local body, the importer shall furnish a certificate issued by the relevant Department of the Central Government or the concerned State Government or the Government of the Union territory, as the case may be, certifying that the said organisation is recognised by the Central Government or the said State Government or the Government of the Union territory and is run on a non-commercial basis.

[F.No. 528/133/03-CUS(TU)]

V. KEZO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

सं. 31/2004-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 82(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु. तारीख 31 मार्च, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 9 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 9. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उसमें अंतर्विष्ट छूट कंप्यूटर और कंप्यूटर परिधीय जिसके अंतर्गत प्रिंटर प्लॉटर, स्कैनर, मानीटर, कीबोर्ड, स्टोरेज यूनिट भी हैं जिन्हें किसी ईकाई द्वारा इनके आयात अथवा अधिप्राप्त करने एवं उनके द्वारा दो वर्ष तक प्रयोग करने के पश्चात् किसी दाता द्वारा दान के रूप में निम्न को दी जाती है " :-

- (i) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित विद्यालय ;
- (ii) किसी संगठन द्वारा गैर-वाणिज्यिक आधार पर संचालित कोई शैक्षणिक संस्थान ;
- (iii) पंजीकृत धर्मार्थ अस्पताल ;
- (iv) सार्वजनिक पुस्तकालय ;
- (v) लोक वित्त पोषित अनुसंधान और विकास स्थापन ;
- (vi) केन्द्र सरकार का किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या किसी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित सामुदायिक सूचना केन्द्र ;
- (vii) केन्द्र सरकार का किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र का किसी स्थानीय संस्था द्वारा संचालित प्रौढ शिक्षा केन्द्र या
- (viii) केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का कोई संगठन ;

बशर्ते कि दाता उस प्रक्रिया के पालन करने का, जो उक्त माल को दाता के एकक से उस के परिसरो को परिवहन करने के लिए दाता के एकक पर अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विहित की जाए ; वचनबद्ध करता है और ऐसे माल का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और उक्त माल का दाता से उसे प्राप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उक्त सहायक आयुक्त या उप आयुक्त की अनुज्ञा के बिना विक्रय, व्ययन, दान, उधार, अदला-बदली या उसे अलग नहीं किया जाएगा व पांच वर्ष की उक्त अवधि के दौरान क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा यादृच्छिक आधार पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कम्प्यूटर वस्तुतः वही है तथा इन्हें दूसरे कार्यों में या अनाधिकृत प्रयोग नहीं किया गया है, निरीक्षण कर सकता है।

बशर्ते कि जहां दाता एक संगठन है लेकिन वह केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय संस्था द्वारा संचालित न हो, दाता एकक, केन्द्र सरकार के संबंधित विभाग या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त संगठन केन्द्र सरकार या उक्त राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा यह गैर-वाणिज्यिक आधार पर संचालित की जाती है।

[फा. सं. 528/133/03-सी.शु. (टी.यू.)]

बी. के.जी. अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु., दिनांक 31 मार्च, 2003 {सा. का. नि. 274 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2003} में प्रकाशित की गई थी।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2004

No. 31/2004-CUSTOMS

G.S.R. 82(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 52/2003-CUSTOMS, dated the 31<sup>st</sup> March, 2003, namely

In the said notification, for paragraph 9, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“9. Notwithstanding anything contained in this notification, the exemption contained herein shall also apply to computers and computer peripherals including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage unit, when donated by the unit two years after their import or procurement and use by the unit, to -

- (i) a School run by the Central Government or, Government of a State or, a Union territory or, a local body;
- (ii) an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization;
- (iii) a Registered Charitable Hospital;
- (iv) a Public Library;
- (v) a Public Funded Research and Development Establishment;
- (vi) a Community Information Centre run by, the Central Government or, Government of a State or, a Union territory or, local body;
- (vii) an Adult Education Centre run by the Central Government or, Government of a State or, a Union territory or, a local body, or
- (viii) an organisation of the Central Government or, a Government of a State or, a Union territory,

subject to the condition that the donor unit undertakes to observe the procedure prescribed by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction over the donor unit, for transport of the said goods from the donor unit to the premises of the donee and such goods shall not be used by the donee for any commercial purposes, and shall not be sold, disposed of, gifted, loaned, exchanged or parted with, without the permission of the said Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs, within a period of five years from the date of receipt of the said goods and during the said period of five years, the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may inspect those organisations on random basis to ensure that the computers are actually there and have not been diverted or put to unauthorized use:

Provided that where the donee is an organisation but not run by the Central Government, Government of a State or a Union territory or a local body, the donor unit shall furnish a certificate issued by the relevant Department of the Central Government or, the concerned State Government or, the Government of the Union territory, as the case may be, certifying that the said organisation is recognised by the Central Government or the said State Government or the Government of the Union territory and is run on a non-commercial basis”.

[F. No. 528/133/03-CUS(TU)]

V. KEZO, Under Secy.

Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No.52/2003-CUSTOMS, dated the 31<sup>st</sup> March, 2003 [G.S.R. 274(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2003].